मैसर्स रामचंद जगदीश चंद

बनाम

भारत और अन्य का संघ

(पी.बी.गजेन्द्रगढ़कर, के. सुब्बा राव,एम. हिदायतुल्ला, जे. सी. शाह और रघुबर दयाल, जे. जे.)

आयात अनुज्ञप्ति-आयात व्यापार नियंत्रण नीति-निर्यात संवर्धन-योजना-आयात पर प्रतिबंध लगाने का राज्य का अधिकार-यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है-अनुज्ञप्ति प्राधिकरण-योजना के तहत दी गई शक्तियां-चाहे गैर-मान्यता प्राप्त हो या मनमाना-आपातकालीन प्रावधान जारी रहना) अध्यादेश, 1946-आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) 8.3 आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955, सं. 3. परिशिष्ट 42, सी. एल. 2 भारत का संविधान अनुच्छेद। 14 , 19 (1) (जी)।

हस्तक्षेपकर्ता-उच्च न्यायालय द्वारा खारिज की गई रिट याचिका को याचिकाकर्ता द्घारा सर्वोच्च न्यायालय द्घारा हस्तक्षेपकर्ता के रूप में सुना जा सकता है-अपील का अधिकार भारत का संविधान-अनुच्छेद। 226 .

भारत सरकार ने "निर्यात संवर्धन योजना" के रूप में जानी जाने वाली एक योजना प्रकाशित की, जिसके अनुसार किसी उद्योग में कच्चे माल के लिए आयात लाइसेंस का मूल्य निर्भर करता है। आयात अनुज्ञप्ति

के लिए आवेदक द्वारा निर्यात की गई वस्तुओं की निर्दिष्ट किस्मों के मूल्यों के लिए आयात निर्यात नियंत्रक को अधिकृत किया गया। यह भी निर्धारित किया गया कि सी. एल. के अधीन आयात और निर्यात नियंत्रक। उप-खण्ड 2 से आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 के परिशिष्ट 42 में भारतीय आर्टसिल्क साड़ियों के मामले में निर्यात मूल्य के 653 प्रतिशत तक और मामले में 100 प्रतिशत तक लाइसेंस जारी करने के लिए कहा गया है। अन्य भारतीय कलात्मक कपड़े। अपीलार्थी फर्म आर सी. एल. पर निर्भर निर्यात और आयात। उप-खण्ड 2 निर्यात का संवर्धन योजना ने उन वस्तुओं के मूल्य के बराबर आयात लाइसेंस के लिए आवेदन किया था जो उसने निर्यात किए थे और विदेशी मुद्रा का उपयोग किया था। कुछ कदाचारों को देखते हुए भारत सरकार ने "निर्यात संवर्धन" योजना को निलंबित कर दिया और निर्यात की गई वस्तुओं के मूल्यों के सत्यापन के लिए एक समिति का गठन किया गया। समिति ने फर्म के दावे की जांच करने के बाद पाया कि कुछ वस्तुओं की दरों को उचित के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, और लगभग आयात लाइसेंस की सिफारिश की गयी। निर्यात की गई वस्तुओं का 45 प्रतिशत मूल्य। निर्यात की गई वस्तुओं के पूर्ण मूल्य के लिए लाइसेंस की निष्फल मांग करने के बाद फर्म आर ने एक रिट याचिका दायर की जिसमें उन्होंने यह प्रस्तुत किया कि लाइसेंस नियंत्रक ने मनमाने ढंग से आयात लाईसेंस का अवमूल्यन कम कर दिया था। उनके आयात लाइसेंस का मूल्य अवैध रूप से कम करके उनके मौलिक अधिकार

का उल्लंघन किया। उन्होंने यह भी दावा किया कि नियंत्रक उनके द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के पूर्ण मूल्य के लिए निर्यात संवर्धन योजना के तहत लाइसेंस देने के लिए बाध्य था और ऐसा करने में विफल रहने पर उसने भेदभाव किया था। उनके खिलाफ, क्योंकि इसी अवधि के दौरान कई अन्य आयातकों को निर्यात की गई वस्तुओं के पूर्ण मूल्य के लिए लाइसेंस दिए गए थे।

मान लिया कि नागरिक का वहन करने का मौलिक अधिकार अनुच्छेद के तहत किसी भी व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय पर। अनुच्छेद 19 (1) (छ) संविधान की धारा निरपेक्ष नहीं है; यह उचित प्रतिबन्धों के अधीन है। ऐसे प्रतिबंध जो आम जनता के हित में राज्य द्वारा लगाए जा सकते हैं।

राज्य का व्यापक क्षेत्र में नियंत्रण लागू करने का अधिकार है। आयात पर आम जनता के हित को तदनुसार अस्वीकार नहीं किया गया है; न ही राज्य के अधिकार को जारी करने के लिए आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केवल केंद्र सरकार द्वारा दिए गए लाइसेंस या सीमा शुल्क परमिट के अनुसार कुछ वस्तुओं के आयात की अनुमति देकर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान करता है, जिसे चुनौती दी जा सकती है। लाइसेंस देने या देने से इनकार करने का अधिकार प्रदान किया जाता है।

राज्य के उच्च अधिकारियों पर और लाइसेंस का अनुदान आयात व्यापार नियंत्रण नीति द्वारा नियंत्रित होता है और विस्तृत प्रावधान किए जाते हैं जिन आधारों पर लाइसेंस से इनकार किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है या रद्द किया जा सकता है और कार्रवाई करने से पहले सुनवाई करने का प्रावधान भी किया जाता है; इस प्रकार अनुज्ञप्ति नियंत्रक के तहत प्रदत्त शक्तियां उप-खण्ड के (3) आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 अप्रमाणित या मनमाना नहीं है।

अनुज्ञप्ति प्राधिकरण को अनुदान देने की शक्ति। केवल सी. एल. में निर्दिष्ट अधिकतम तक के लाइसेंस। उप-खण्ड 2 परिशिष्ट 42 अपने आप में एक नहीं है। अनुचित प्रतिबंध, और न ही सभी आवेदनों की जांच का निर्देश देने वाली अधिसूचना एक अनुचित प्रतिबंध लगाने के बराबर होगी। खंड नियंत्रक को अधिकार देता है, यह निर्यातक द्वारा दावा की गई राशि (अधिकतम निर्धारित के अधीन) के लिए लाइसेंस जारी करने के लिए निर्यातक के कहने पर प्रवर्तनीय दायित्व नहीं लगाता है। शक्ति स्पष्ट रूप से विवेकाधीन है और नियंत्रक द्वारा निर्यात की गई वस्तुओं के मूल्य के केवल 45 प्रतिशत के लिए लाइसेंस देने का आदेश अनुच्छेद के तहत याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। अनुच्छेद 19 (1) (छ) एक अनुचित प्रतिबंध लागू करने का संविधान में प्रावधान है।

यह भी निर्धारित किया गया कि दिखाने के लिए सबूत के अभाव में कि पीड़ित व्यक्ति और समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के बीच भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया था, उक्त अनुच्छेद का कोई उल्लंघन नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 14 संविधान जो समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के बीच मनमाने भेदभाव के खिलाफ गारंटी प्रदान करता है।

यह व्यवस्था भी दी गयी कि जहां एक आवेदन जो परमादेय याचिका में निर्देश पारित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय द्घारा खारिज कर दिया गया है। ऐसे में पीडित पक्ष को एकमात्र उपचार इसकी अपील है। उसे इसे आदेश को हस्तक्षेपकर्ता न्यायालय द्घारा नहीं सुना जा सकता है।

आपराधिक न्याय निर्णयः की लिखित याचिका संख्या 1/1960

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए।

ए. वी. विश्वनाथ शास्त्री, के. के. जैन और गणपत राय, याचिकाकर्ताओं की ओर से।।

सी. के. दफ्तरी, सॉलिसिटर-भारत के महाधिवक्ता, वी. ए. और टी. एम. सेन उत्तरदाताओं

के लिए सैयद मोहम्मद।

1961. 8 अगस्त। न्यायालय द्घारा निर्णय पारित किया गया।

न्यायमूर्ति शाह। निर्यात और आयात पर नियंत्रण पिछले दौरान एक आपातकालीन उपाय के रूप में लगाया गया। कुछ वस्तुओं के संबंध में अन्तिम स्तर पर रखा गया था। भारत की रक्षा की समाप्ति के बाद जीवित आपातकालीन प्रावधानों द्वारा नियम (निरंतरता) अध्यादेश, 1946 जिसे बाद में आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। (18/1947), एस द्वारा। (3) अधिनियम के अनुसार, केंद्रीय सरकार को अधिनियम में प्रकाशित आदेश द्वारा अधिकृत किया गया था। मामलों के वर्ग, और ऐसे अपवादों के अधीन, यदि जैसा कि आदेश द्वारा या उसके तहत किया जा सकता है, अन्य रूप से वस्तुओं का आयात, निर्यात, परिवहन नियमों के प्रावधानों में XXX में से। कोई भी निर्दिष्ट विवरण। उप धाराओं द्वारा। उप-खण्ड(2) एस. 3 . , यह नियम प्रदान किया गया था कि सभी वस्तुएं जिन्हें उपधाराओं के तहत एक आदेश। (1) लागू माना जाएगा। ऐसी वस्तुएँ जिनका आयात या निर्यात होता है। समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 8,19 के तहत प्रतिबंधित है या जिन्हें प्रतिबंधित किया गया है। आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के 8.3 के तहत प्राधिकरण का प्रयोग करना। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की। विभिन्न प्रकार के निर्यात और आयात को नियंत्रित करना वस्तुएँ। दिनांकित एक समेकित आदेश द्वारा 7 दिसंबर, 1955, जिसे आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के रूप में जाना जाता है, के आयात पर प्रतिबंध सी. एल. द्वारा कुछ वस्तुओं को लगाया गया था।

सीएल द्वारा। (3) आदेश द्घारा यह प्रावधान किया गया था कि आदेश में अन्यथा प्रदान किए गए प्रावधान को छोड़कर, कोई भी व्यक्ति अनुसूची (1) में निर्दिष्ट विवरण के किसी भी सामान का आयात नहीं करेगा, सिवाय इसके कि केंद्र सरकार द्वारा या अनुसूची (II) में निर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा दिए गए लाइसेंस या सीमा शुल्क मंजूरी परमिट के तहत और उसके अनुसार। आयात को नियंत्रित करने की योजना को लागू करने के लिए सी. एल. एस. में विविध प्रावधान किए गए थे। उप-खण्ड(3) आयात (नियंत्रण) आदेश के नियम 11 तक।

भारत सरकार हर छह महीने में अपनी आयात नीति जारी करती है। सरकारी राजपत्र में अनुज्ञप्ति की पात्रता के लिए प्रक्रिया और शर्तें इसे "आयात व्यापार नियंत्रण नीति" कहा जाता है। यह नीति स्पष्ट रूप से घरेलू उपभोग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। आयात की जाने वाली वस्तुएं विदेशी मुद्रा की स्थिति और पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालती है। अक्टूबर 1958 की अनुज्ञप्ति अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति के पैरा 51 द्वारा मार्च, 1959 में "निर्यात संवर्धन" की एक योजना तैयार की गई थी, जिसमें आयातक देशों द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की निर्दिष्ट किस्मों के मूल्य के आधार पर आयात की अनुमति दी गई थी। उस परिच्छेद में यह पढ़ा गया था कि कुछ मदों में, अंतर-संबंध आयात और निर्यात के बीच प्रत्यक्ष था और अंतरंग और कुछ निर्मित वस्तुओं के निर्यात की क्षमता काफी हद तक

उस सुविधा पर निर्भर करती थी जिसके साथ निर्यातक या निर्माता निर्माण में आवश्यक बुनियादी कच्चे माल की खरीद कर सकता था। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। इस तरह की वस्तुओं के निर्यात के लिए 76 लोगों को विशेष आयात लाइसेंस देने के लिए एक योजना तैयार की गई थी। निर्यात किए गए उत्पाद के आयातित कच्चे माल के घटक को प्रतिस्थापित करें या बड़े निर्यात के लिए प्रोत्साहन प्रदान करें।

आर्टसिल्क यार्न और आर्टसिल्क कपड़े ढके हुए थे। निर्यात संवर्धन योजना द्वारा। परिशिष्ट 42 में, सी. एल. 2 अक्टूबर 1958 से मार्च 1959 के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति में कहा गया थाः

> "निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारतीय कलात्मक कपड़े, साड़ियां, वस्त्र, होजरी और अन्य आर्टसिल्क का निर्माण,यह आयात लाइसेंस देने का निर्णय लिया गया है। निर्यात संवर्धन के तहत बंदरगाहों पर रुपये का निम्नलिखित प्रतिशत विदेशी मुद्रा के समतुल्य एफ का आधार। ओ। बी। कलात्मक वस्तुओं का मूल्य निर्यात किया गया, या सीमा शुल्क द्वारा मूल्यांकन किया गया मूल्य, जो भी कम हो।
>
> (i) 66-2/3 प्रतिशत के मामले में भारतीय कलात्मक साड़ियां,

(ii) अन्य के मामले में 100 प्रतिशत भारतीय सहित भारतीय कलात्मक कपड़े आर्टसिल्क होजरी का सामान "।

याचिकाकर्ता, मेसर्स। राम चंद जगदीश चंद निर्यातक के रूप में व्यवसाय में लगी एक फर्म हैं।और आयातक। अक्टूबर 1958 की अवधि में मार्च 1959, याचिकाकर्ताओं ने सिंगापुर को निर्यात किया, बुश क्लॉथ, ग्लास नायलॉन, आर्ट सिल्क पीस कुल सी. आई. एफ. का सामान और उच्च श्रेणी का नायलॉन। रुपये का मूल्य। रू,10,817/- , और सी. एल. पर भरोसा करते हैं। उप-खण्ड(2) में उल्लिखित निर्यात संवर्धन योजना आयात व्यापार नियंत्रण नीति का आह्वान किया गया। आयात नियंत्रक आर्टसिल्क के लिए लाइसेंस जारी करेगा। रु. के लिए धागा। 4,04, 218.62 एन. पी. और रु. 3,03, 490.93 एन. पी. विशेष रूप से फरवरी के महीनों के लिए और मार्च में 1959। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि उन्होंने निर्यात संवर्धन योजना के अनुसार सिंगापुर को दलहन के सामान का निर्यात किया था और शुद्ध कमाई की थी। रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा। रू,07, 709.55 एन. पी. और यह कि वे उस राशि के आर्टसिल्क धागे के लिए आयात लाइसेंस के हकदार थे। सितंबर 1959 में, याचिकाकर्ताओं को सहायक द्वारा सूचित किया गया था। आयात और निर्यात नियंत्रक जो एक कंसोटी है। फरवरी के महीनों के लिए दिनांकित लाइसेंस और मार्च, 1959 में उन्हें एक करोड़ रुपये मूल्य के दलहन के सामान के आयात के लिए अनुमति दी गई थी।

ऐसा प्रतीत होता है कि भारत सरकार को कुछ कदाचारों का पता चला है। आर्टसिल्क धागे के आयातकों ने 9 मार्च, 1959 से निर्यात संवर्धन योजना को निलंबित करते हुए घोषणा की कि जो आवेदन लंबित थे। बंदरगाह लाइसेंस प्राधिकरणों के साथ एक समिति द्वारा जांच की जाएगी और मई 1959 में भारत सरकार ने इसके सत्यापन के लिए एक समिति नियुक्त की। निर्यात की गई वस्तुओं का मूल्य। याचिकाकर्ताओं ने समिति के समक्ष उपस्थित हुए और निर्यात किए गए कपड़े के बराबर रुपये के लिए उनके दावे के समर्थन में दस्तावेजी परामर्श साक्ष्य प्रस्तुत किए। समिति ने याचिकाकर्ताओं द्वारा निर्यात किए गए "फ्लॉक प्रिंटेड नायलॉन डाईड" कपड़े को जिस दर पर निर्यात किया गया था, उसे उचित माना, लेकिन उनके विचार में, जिस दर पर "बुश शर्ट क्लॉथ" का निर्यात किया गया था, उसे उचित के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता था और निर्यात संवर्धन योजना के उद्देश्य से, उस कपड़े के मूल्य की गणना रुपये की दर से की जानी चाहिए। 1.50 एन. पी. 36 "चौड़ाई का प्रति यार्ड। लाइसेंस नियंत्रक ने समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया और याचिकाकर्ताओं को 500 रुपये का आयात लाइसेंस जारी किया था। याचिकाकर्ताओं ने निर्यात किए गए माल के मूल्य के लिए लाइसेंस की निष्फल मांग करने के बाद, यह याचिका उक्त अनुच्छेद के तहत दायर की। आयात के मुख्य नियंत्रक को निर्देश देने वाले आदेश या निर्देश के लिए संविधान की धारा और याचिकाकर्ताओं को एक आयात फरवरी और

मार्च 1959 के महीनों के लिए संबंधित पिछले महीनों में उनके द्वारा निर्यात किए गए माल के 100% के समतुल्य लाइसेंस और वैकल्पिक रूप से, अभिलेखों और कार्यवाहियों को बुलाते हुए प्रमाण पत्र का एक रिट जारी करने के लिए जिसके परिणामस्वरूप रुपये के मूल्य का लाइसेंस जारी किया गया और इसे रद्द करने और याचिकाकर्ताओं को उनके द्वारा दावा की गई पूरी राशि के लिए लाइसेंस देने के आदेश के लिए। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि लाइसेंस नियंत्रक ने निर्यात संवर्धन योजना के तहत उनके आयात लाइसेंस के मूल्य को मनमाने ढंग से कम कर दिया था और इस तरह व्यवसाय करने के उनके मौलिक अधिकार का गैरकानूनी रूप से उल्लंघन किया था। यह भी दावा किया कि नियंत्रक निर्यात के तहत आर्टसिल्क धागे के आयात के लिए लाइसेंस देने के लिए बाध्य था। थोक द्वारा निर्यात की गई वस्तुओं के पूर्ण मूल्य के लिए संवर्धन योजना, और ऐसा करने में विफल रहने पर, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भेदभाव का व्यवहार किया गया था, क्योंकि इसी अवधि के दौरान व्यापार में याचिकाकर्ताओं के प्रतिद्वंद्वी आर्टसिल्क धागे के कई अन्य आयातकों को "उनके निर्यात के 85 से 100 प्रतिशत के बीच" राशि के लिए लाइसेंस दिए गए थे। अपनी याचिका के पैराग्राफ 22 में, याचिकाकर्ताओं ने ऐसे आठ निर्यातकों के नाम, ऐसे निर्यातकों को दी गई राशि और प्रतिशत निर्धारित करते हुए एक तालिका प्रस्तुत की। अनुच्छे के तहत किसी भी व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय को जारी रखने का अधिकार है।

नागरिकों का मौलिक अधिकार। 19 (1) (छ) संविधान का अनुच्छेद निरपेक्ष नहीं हैः यह उचित प्रतिबंधों के अधीन है जो आम जनता के हित में राज्य द्वारा लगाए जा सकते हैं। आयात पर आम जनता के व्यापक हित में नियंत्रण लागू करने के राज्य के अधिकार से तदनुसार इनकार नहीं किया गया हैः न ही राज्य को आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 जारी करने का अधिकार है, जिसमें केवल लाइसेंस या सीमा शुल्क परमिट के अनुसार कुछ वस्तुओं के आयात की अनुमति देकर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है। केंद्र सरकार को चुनौती दी गई। इसका सुझाव श्री विश्वनाथ ने कुछ हल्के-फुल्के अंदाज में दिया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से शास्त्री ने कहा कि सी. एल. के तहत शक्ति प्रदान की गई जो उप-खण्ड (3) आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के मामले में गैर-मान्यता प्राप्त शक्ति थी जिसमें प्रतिशत निर्धारित करना और उस हद तक, प्राधिकरण ने व्यवसाय करने की स्वतंत्रता पर अनुचित प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन लाइसेंस देने या देने से इनकार करने का अधिकार राज्य के उच्च अधिकारियों को दिया जाता है और लाइसेंस देने का अधिकार आयात व्यापार नियंत्रण नीति द्वारा नियंत्रित होता है जो समय-समय पर जारी की जाती है और आयात (नियंत्रण) आदेश में विस्तृत प्रावधान किए जाते हैं जिनके आधार पर लाइसेंस देने से इनकार किया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है या रद्द किया जा सकता

है। आदेश के 6 से 9 सी. एल. एस. के तहत कार्रवाई करने से पहले लाइसेंस को वहन करने का प्रावधान हैं। आदेश 6 से 9 बनाया है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रदत्त शक्ति अप्रमाणित या मनमानी है।

याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा गंभीरता से प्रचारित तर्क यह था कि सी. एल. पर भरोसा किया गया था। उप-खण्ड 2 परिशिष्ट 42 में आयात व्यापार नियंत्रण नीति में कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं ने आर्टसिल्क कपड़ों का निर्यात किया था और विदेशी मुद्रा अर्जित की थी, और वे अच्छे और पर्याप्त कारणों को छोड़कर, निर्यात किए गए आर्टसिल्क कपड़ों के मूल्य के 100% की पूरी सीमा तक आयात लाइसेंस से वंचित नहीं हो सकते थे। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने विभिन्न व्यापारियों से माल खरीदा और अर्जित विदेशी मुद्रा का निर्यात करके जो उनके बैंकरों द्वारा उनके खाते में विधिवत जमा किया गया था, और आयात लाइसेंस को निर्यात किए गए माल के मूल्य का लगभग 45 प्रतिशत तक कम करने के लिए, राज्य ने कार्यकारी आदेश द्वारा व्यापार करने के उनके अधिकार पर अनुचित प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन सीएल के तहत। उप-खण्ड 2 में उल्लिखित निर्यात संवर्धन योजना परिशिष्ट 42 जहाँ तक यह आर्टसिल्क धागे के आयात के लिए लाइसेंसों से संबंधित है, आयात नियंत्रक उस खंड में निर्दिष्ट प्रतिशत तक लाइसेंस देने के लिए अधिकृत हैः कोई अधिकार नहीं है। निर्यात की गई वस्तु के पूर्ण मूल्य के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए निर्यातक को बनाया गया। जिसके तहत सी.

एल. 2 योजना की शक्ति नियंत्रक के पास है। माल बैल के एफ. ओ. बी. मूल्य के आधार पर अर्जित विदेशी मुद्रा के समतुल्य रुपये की 100% तक की किसी भी राशि के लिए लाइसेंस प्रदान करना है जिसे पोर्ट किया गया। उस खंड के अनुसार, निर्यातक को किसी भी आयात लाइसेंस का दावा करने का विकल्प नहीं दिया जाता है। माल के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा के मूल्य से अधिक राशि नहीं चाहिए। खंड नियंत्रक को अधिकार देता है, ऐसा नहीं है। निर्यातक द्वारा दावा की गई राशि (अधिकतम निर्धारित के अधीन) के लिए लाइसेंस जारी करने के लिए निर्यातक के कहने पर उस पर एक दायित्व अधिरोपित करें जो लागू किया जा सके। शक्ति स्पष्ट है। विवेकाधीन। यह सच है कि विवेकाधिकार का प्रयोग उचित रूप से किया जाना चाहिए न कि मनमाने ढंग से। लाइसेंस प्राधिकरण आम तौर पर निर्यात की गई वस्तुओं के मूल्य के 100% के लिए आयात लाइसेंस जारी करेगा। लेकिन कठिन विदेशी मुद्रा स्थिति या राज्य के सामान्य हित को प्रभावित करने वाले अन्य मामलों जैसे विशेष विचारों को ध्यान में रखते हुए, निर्यातकों को कम प्रतिशत के लिए आयात लाइसेंस दिए जा सकते हैं। लेकिन "रुपये के समतुल्य के निम्नलिखित प्रतिशत तक" अभिव्यक्ति के उपयोग से आयात लाइसेंस देने के लिए निर्यात किए गए माल के मूल्य का एक प्रतिशत मनमाने ढंग से तय करने की शक्ति प्रदान नहीं की जाती है।

याचिकाकर्ताओं को 3,19,354 /रुपये में लाइसेंस देने में किस अधिकार का प्रयोग किया गया है। मनमाने ढंग से या यह किसी तर्कसंगत रूप से स्पष्ट सिद्धांत द्वारा समर्थित है? आयात और निर्यात के उप मुख्य नियंत्रक राम मूर्ति शर्मा ने अपने हलफनामे में कहा कि निर्यात संवर्धन योजना का गलत लाभ आर्टसिल्क कपड़ों के कुछ निर्यातकों ने उठाया थाः भारत सरकार द्वारा यह पाया गया कि निर्यातकों द्वारा कृत्रिम सुपर कोर्ट रिपोर्ट जैसी "सट्टा" वस्तुओं के आयात के उद्देश्य से चालान मूल्य या कृत्रिम रेशम के कपड़ों को मूल्य के 100% से अधिक बढ़ाया गया था। रेशम का धागा। शर्मा ने कहा कि "381 के मुकाबले जनवरी-जून, 1957 की अवधि के दौरान हजारों गज के कृत्रिम रेशम के कपड़ों का निर्यात किया गया, जिसका मूल्य लगभग रु456 हजार यानी लगभग Rs.1-2-0 प्रति यार्ड पर व्यापारियों ने अक्टूबर मार्च 1959 के दौरान ऐसी वस्तुओं के निर्यात के लिए मूल्य में वृद्धि को रु। 2-9-0 प्रति यार्ड ताकि 986 हजार गज के निर्यात के लिए, दिखाया गया चालान मूल्य 28,799 हजार रुपये था, भले ही थोक बाजार में माल की वास्तविक कीमत उन दोनों के बीच उस हद तक बिल्कुल नहीं बढ़ी थी। यह लगभग 11 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इस वृद्धि के खिलाफ, निर्यातकों द्वारा चालान की गई कीमत में वृद्धि ने इसी अवधि के दौरान 125% से अधिक की वृद्धि दिखाई। यह स्पष्ट रूप से बताएगा कि उपरोक्त व्यापारियों द्वारा वृद्धि केवल आयात के लिए उच्च मूल्य के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की दृष्टि

से दिखाई गई थी। "आर्ट सिल्क यार्न" जैसी सट्टा वस्तु। इस साक्ष्य पर भरोसा करते हुए, संघ के वकील ने तर्क दिया कि निर्यात संवर्धन की यह विकृति आर्टसिल्क धागे के लिए आयात लाइसेंस की जांच उस ओर से नियुक्त समिति द्वारा की जानी चाहिए। समिति ने याचिकाकर्ताओं सहित 1106 पक्षों के मामलों की जांच की और याचिकाकर्ताओं को 5 लाख रुपये का लाइसेंस दिया गया और आयात लाइसेंस के मूल्य को कम करके, कोई मौलिक नहीं बल्कि अनुच्छेद के तहत याचिकाकर्ताओं का अधिकारों का अनुच्छेद 19 संविधान का उल्लंघन किया गया था।

लाइसेंस के लिए आवेदनों की जांच निर्यात संवर्धन के दुरुपयोग का दृष्टिकोण योजना और इसके परिणामस्वरूप लाइसेंस प्रदान करना है। इस तरह की जांच को सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट लागू करने के रूप में नहीं माना जा सकता है जो कि अनुचित प्रतिबंध है। राज्य का कर्तव्य इतना है कि विदेशी मुद्रा अर्जित करने से संबंधित अपने निर्यात व्यापार को बनाए रखना और समेकित करना। यदि बड़ी मात्रा में सामान अत्यधिक मात्रा में फेंका जाता है। विदेशी बाजारों में कीमतें अस्थायी रूप से बढेगी। अंतिम परिणाम में मांग का निर्यात व्यापार राज्य को नुकसान हो सकता है। अगर फायदा उठाएँ विदेशी बाजार में अस्थायी मांग के अनुसार फायदा उठाया जाता है। निर्यातक अत्यधिक मूल्य वसूलते हैं जो उचित नहीं हैं वास्तविक आधार पर उचित लाभ के अनुरूप वस्तुओं का मूल्य और अर्जित लाभ को सट्टा वस्तुओं में निवेश करने की कोशिश करना जिससे देश की आंतरिक

अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ जाए, राज्य को निर्यातकों को रोकने के लिए कदम उठाने में उचित ठहराया जा सकता है।इस तरह के अत्यधिक लाभ का लाभ प्राप्त करना वस्तुओं के आयात के लिए सुविधाओं का खर्च उठाने से इनकार करना निर्यातक जो निर्यात पर निर्भर रहना चाहते हैं बढ़ी हुई दरों पर माल का मूल्य है। शर्मा के हलफनामे से पता चलता है कि कई मामलों में, विदेश में आयात करने वाली फर्म केवल एक "निर्यातक घराने की सहयोगी चिंता, और निर्यातकों ने इसे बढ़ाने के उपाय को अपनाया उनके द्वारा प्राप्त अतिरिक्त मूल्य को समायोजित करने के उद्देश्य के साथ मूल्य निर्धारित किया। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ निर्यात संवर्धन के दायरे में आने वाले निर्यातक कीमतों को बढ़ाने की योजना न केवल बहुत अधिक के लिए वस्तुओं की सट्टा किस्मों के आयात के लिए पाई गई। उचित वास्तविक कीमतों की तुलना में बहुत अधिक मूल्य, लेकिन अधिकारियों द्वारा भी संदेह किया गया था। बिना खुलासा किए विदेशी परिसंपत्तियों को वापस भेजना राज्य के लिए वैसा ही जैसा कानून द्वारा आवश्यक है। यह नहीं हो सकता। अतः यह कहा जाए कि प्रदत्त शक्ति लाइसेंस देने वाले प्राधिकरण केवल एक सीमा तक के लिए लाइसेंस प्रदान करेंगे। सीएल में निर्दिष्ट अधिकतम। योजना अपने आप में एक अनुचित प्रतिबंध है और न ही सभी आवेदनों की जांच का निर्देश देने वाली अधिसूचना यह एक अनुचित प्रतिबंध लगाने के बराबर है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने हालांकि कहा कि नियंत्रक ने इस पर कोई सबूत नहीं दिया

था।अभिलेख जो याचिकाकर्ताओं के पास माल के लिए है। उनके द्वारा भारतीय बाजार में खरीदे गए माल का भुगतान भारतीय रूपए में नहीं किया गया। एन. पी. या कि उसका कोई हिस्सा प्रतिनिधि है। भेजी गई विदेशी परिसंपत्तियों का पुनर्भुगतान करने का इरादा कानून के विपरीत है। जैसा कि वकील ने प्रस्तुत किया कि मेसर्स।वी. एम.एस. अब्दुल रज़ाक एंड कंपनी जिसे सामान दिया गया था। भेजे गए थे एक "गहन चिंता" नहीं हैं। याचिकाकर्ताओं और डिप्टी के हलफनामे में आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक इस बात से इनकार किया कि याचिकाकर्ताओं को पूरा मूल्य प्राप्त हुआ था। वह मूल्य जिसके लिए उनके द्वारा माल का निर्यात किया गया था।लेकिन याचिकाकर्ताओं के मामले पर विचार करते हुए,समिति ने कहाः

"पार्टी ने बुश शर्ट का कपड़ा खरीदा है। जे. सी. वकारिया एंड संस, गोवर्धनदास ईश्वरदास से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एजेंसी, अग्रवाल ब्रदर्स और कलकत्ता सिल्क मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, लिमिटेड दरें। रुपये से भिन्न होता है। जो कि 3.87 रु. तक है। 3.92 परिशिष्ठ में .XXXX न तो खरीद वाउचर और न ही निर्यात चालान में शामिल हैं न तो कोई विवरण दें और न ही कोई विचार दें कि क्या सामग्री नायलॉन, रेयॉन, निनॉन आदि थी।

समिति ने यह भी पाया कि पेटी टियोनर पर्याप्त न्याय देने में सक्षम नहीं थे, आर्ट सिल्क बुश शर्टिंग क्लॉथ की कीमतों का निर्धारण। नमूनों को सापेक्ष शुद्धिकरण के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। वाउचर या

निर्यात चालान का पीछा करें "। तब वे इंगित किया कि एम/एस के साथ पत्राचार। अब्दुल रज़ाक एंड कंपनी ने कोई "औचित्य" नहीं दिया न ही माल को जोड़ने के लिए कोई विवरण भेजी गई सामग्री के साथ था", और इनके प्रकाश में समिति ने सिफारिश की कि आयात के उद्देश्यों के लिए बुश शर्ट कपड़े का मूल्य लाइसेंस की गणना रुपये की दर से की जानी चाहिए। 1. 50 एन. पी. प्रति यार्ड। यह कुछ हद तक दुर्भाग्यपूर्ण है कि कॉम की मिट्टी ने उनके द्वारा दिए गए कारणों में यह नहीं कहा है कि टी1.50 एन. पी. में प्रचलित बाजार दर थी। उसके समय बुश शर्ट कपड़े का सम्मान भारतीय बाजार में निर्यात किए जाने में था। लेकिन पैराग्राफ 22 में उत्तरदाताओं के शपथ पत्र में यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता फर्म को एक्स के बराबर लाइसेंस दिया गया है। 100 % जिस मूल्य पर पहुँचा गया है। द्वारा प्रभावित निर्यात का उचित मूल्य है।

याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि भारत की समिति का आचरण मन माना था। उनका तर्क है कि निर्णय इसके बाद लिया गया था। भारतीय में उचित मूल्य का पता लगाना निर्यात की गई वस्तुओं के सामग्री समय पर बाजार याचिकाकर्ताओं द्वारा ऐसा नहीं किया न ही अदालत के समक्ष कोई भी स्वतंत्र सबूत रखा गया। यह दिखाने के लिए कि "बुश शर्ट" की वर्तमान बाजार दर कपड़ा "जो काफी हद तक निर्यात किया गया था, पार कर गया। जिसकी दर 1. 50 एन. पी. 36 "का प्रति यार्ड चौड़ाई है। इन परिस्थितियों में हम यह मानने में न्यायसंगत है कि

समिति ने मूल्य पर पहुंचने में एक मनमाना निर्णय लिया। पुनर्नियुक्ति के उद्देश्य से निर्यात किया गया साड़ी शर्ट का कपड़ा आयात लाइसेंस के अनुदान में सुधार करना।

यह तर्क कि आदेश पारित किया गया। केवल 45 प्रतिशत के लिए लाइसेंस देने वाला नियंत्रक निर्यात की गई वस्तुओं का मूल्य निधि का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद के तहत याचिकाकर्ताओं का मानसिक अधिकार। अनुच्छेद 19 (1) (जी) अनुचित प्रतिबंध लगा कर नहीं किया जा सकता है इसलिए स्थिर रहें।

क्या यह तथ्य है कि याचिकाकर्ताओं ने कुल के लगभग 45 प्रतिशत के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया। निर्यात की गई वस्तु का मूल्य उन्हें अनुच्छेद के संरक्षण का अधिकार देता है। निर्यात संवर्धन के तहत योजना, याचिकाकर्ताओं ने कला के सामान का निर्यात किया है। सामान्य पाठ्यक्रम आयात लाइसेंस के हकदार हैं। निर्यात किए गए माल के मूल्य के 100% के लिए जब तक कि लाइसेंस के मूल्य में कमी आई थी। कुछ परिस्थितियों के कारण आयात के लिए जैसे कि विदेशी मुद्रा में सामान्य गिरावट किसी विशेष के संरक्षण के लिए स्थिति या आवश्यकता मुद्रा या एक को उचित ठहराने वाली अन्य परिस्थितियाँ सी. एल. में निर्धारित अधिकतम से प्रस्थान। निर्यात संवर्धन योजना का परिशिष्ट 42। कटौती याचिकाकर्ताओं या उस समूह के लिए व्यक्तिगत आधारों पर भी उचित हो

सकती है जिससे वे संबंधित थे। किसी भी कदाचार या हाथ से किए गए लेन-देन में इस तरह की कमी की आवश्यकता हो सकती है।

यह उत्तरदाताओं का मामला था कि कई निर्यातक कदाचार के दोषी थे और एक दृष्टिकोण या तो कलात्मक वस्तुओं में अटकलें लगाने के लिए या गैरकानूनी रूप से विदेशी परिसंपत्तियों को वापस करने के लिए, निर्यात किए गए माल का मूल्य अनुचित रूप से बढ़ाया गया था। नियुक्त समिति द्वारा पारित आदेश में भारत सरकार, मामले से निपट रही है। यह देखा गया कि याचिकाकर्ताओं के कुछ फर्मों के साथ व्यावसायिक संबंध थे और जिन दरों पर बुश शर्ट का कपड़ा खरीदा गया था, वे रुपये से भिन्न थे। 3.87 रु. तक। 3.92 एन. पी. समिति इस बात से संतुष्ट नहीं थी कि दस्तावेजी साक्ष्य याचिकाकर्ताओं द्वारा उनके द्वारा निर्यात किए गए माल से संबंधित प्रस्तुत किया गया। इन निष्कर्षों से पता चला कि समिति के विचार में यह मानने का कारण था कि याचिकाकर्ताओं का दावा था कि उन्होंने लगभग कीमतों के हिसाब से सामान खरीदा था। जिन पर उनका निर्यात किया गया था, उन्हें तैयार नहीं किया गया था। तदनुसार समिति ने सिफारिश की कि "बुश शर्ट कपड़े" के मूल्य की गणना रुपये की दर से की जानी चाहिए। 1.50 एन. पी. प्रति यार्ड। यह सच है कि अभिलेख पर कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। यह दर्शाता है कि यह वर्तमान बाजार दर थी, लेकिन अदालत यह अभिनिर्धारित करने में उचित हो सकती है कि समिति के सदस्य जो महत्वपूर्ण थे। कलात्मक वस्तुओं के व्यापार से संबंधित थे।

वर्तमान बाजार दरों के अनुरूप कपड़ा जो याचिकाकर्ताओं द्वारा निर्यात किया गया था।

भारत संघ के वकील ने हमारे सामने अपना पक्ष रखा है। रिपोर्ट की सुनवाई के दौरान आठ में से सात के संबंध में समितिजिन निर्यातकों के बारे में याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि जिनके पूर्ण मूल्य के लिए आयात लाइसेंस दिया गया वे निर्यात करते हैं कि राजस्थान निर्यातक और आयातक, कलकत्ता के सम्बन्ध में समिति ने रिपोर्ट रखी है जबिक याचिका में हमारे समक्ष नहीं रखी गयी है न ही यह तुरंत उपलब्ध है। जिसके अवलोकन पर के संबंध में समिति की रिपोर्ट अन्य निर्यातकों का दावा है कि याचिकाकर्ताओं में से कि रघुनाथ राय पियारीलाल के पूरे मूल्य के लिए आयात लाइसेंस दिया गया था। निर्यात किया गया माल सही नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि रिकॉर्ड है कि एफ. ओ. बी. मूल्य का केवल 40 प्रतिशत ग्लास नायलॉन के लिए लिया जाना था जो कि वस्तुतः, आवेदन संख्या 35 के संबंध में, 40 प्रतिशत एफ. ओ. बी. मूल्य इस उद्देश्य के लिए लिया जाना था। आयात लाइसेंस देना। यह सच है कि अन्य आयातकों प्रेमसुखदास के मामले सीताराम, भारतीय निर्यातक और आयातक निगम टियन, एम/एस। यूनिवर्सल वॉच एम्पोरियम, मेसर्स। जवाहर बुनाई होजरी, एम/एस। वस्त्रालय लिमिटेड और एम/एस। अगरवाला ट्रेडिंग कं, लिमिटेड, समिति लाइसेंस। अतः यह माना जा सकता है कि इन आयातकों को 100% के लिए लाइसेंस दिया गया था। माल का निर्यात मूल्य. लेकिन

समिति ने जाे कारण दिए हैं जो प्रथम दृष्टया प्रतीत होते हैं, इन एक्सपोटर्स के दावों को स्वीकार करने के लिए अच्छा है। यदि उनके सामने रखी गई सामग्री पर, समिति संतुष्ट थी कि कुछ कदाचार या हाथ से काम न लेना याचिकाकर्ता साक्ष्य प्रस्तुत करने से पहले नेतृत्व किया, उन्होंने समिति को यह ठहराते हुए उचित ठहराया कि निर्यात की गई वस्तुएँ उस मूल्य की नहीं थीं जिसका उन्होंने दावा किया था। याचिकाकर्ताओं ने अपने चालान में एक आदेश की सिफारिश की। जिसके लिए आयात लाइसेंस दिया जा सकता है। जिसके आधार पर गणना की गई बुश शर्ट कपड़े का मूल्य री. 1. 50 एन. पी. प्रति यार्ड भेदभाव के बराबर नहीं है। याचिकाकर्ताओं के साथ प्राकृतिक व्यवहार किया गया है। समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के बीच कानून-मनमाने भेदभाव के खिलाफ अनुच्छेद 14 समान सुरक्षा की गारंटी देता है। समिति के समक्ष रखी गई सामग्री, वहाँ थी। यह दिखाने के लिए सबूत कि द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड। याचिकाकर्ता असंतोषजनक थे; वे इस बात से संतुष्ट नहीं थे कि याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने सामान खरीदने के लिए जो कीमत चुकाई थी, वह वास्तव में चुकाई गई थी। अगर यह साबित करने के लिए सबूत थे कि अन्य व्यक्तियों के संबंध में जो समिति की राय में याचिकाकर्ताओं द्वारा अपनाए गए तरीके से कीमतों में वृद्धि करते पाए गए और फिर भी नियंत्रक ने उन व्यक्तियों को निर्यात की पूरी राशि के लिए आयात लाइसेंस प्रदान किए थे। मूल्य या उस प्रतिशत से काफी

अधिक प्रतिशत जिसके लिए याचिकाकर्ताओं को आयात लाइसेंस दिया गया था, भेदभाव का मामला बाहर किया जा सकता था; लेकिन तथ्यों की अनुपस्थिति में इस तरह के सबूतों के बारे में, हम नहीं सोचते कि कोई मामला भेदभाव किया गया है।

अतः याचिका विफल हो जाती है जो खर्चे सहित खारिज की जाती है। मेसर्स एम० शम्स और हस्तक्षेप के लिए कंपनी आवेदन खारिज किया जाता है, क्योंकि 1960 का विविध अनुप्रयोग आवेदन सं. 264 जो उच्च न्यायालय में आवेदकों द्वारा दायर किया गया था। मैंडमस के एक रिट के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय न्यायपालिका, अनुच्छेद 226 के तहत आवेदन उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था और उपचार आवेदकों को इस पर अपील इस न्यायालय में संस्थित करनी है।

याचिका खारिज की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवाद **विनोद कुमार गिरि (न्यायिक अधिकारी)** द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उददेश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उददेश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उददेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।